OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 5 Issue 4 [Jul-Aug] Year 2026*

Research Article

अमेरिका–ईरान संघर्ष और भारत पर उसके आर्थिक प्रभाव: ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, मुद्रास्फीति और भू-आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण

दशरथ प्रसाद अहिरवार [1*], विनीता अहिरवार [2], डॉ. पदम नारायण [3], डॉ. राजवीर सिंह किरार [4]

[1] शोधार्थी, अर्थशास्त्र, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्व विद्यालय छतरपुर, मध्य प्रदेश, भारत

[2] शोधार्थी, अर्थशास्त्र, जीवाजी विश्व विद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

[3] सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश, भारत

[4] प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महा. मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author: * दशरथ प्रसाद अहिरवार

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22249627

सारांश

अमेरिका-ईरान संघर्ष के भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का यह शोध-पत्र विश्लेषण करता है। Jun. 2025 में ईरान पर अमेरिकी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले ने दिखाया कि दोनों देशों के बीच तनाव केवल प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव तक सीमित नहीं है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है: भारतीय रिजर्व बैंक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और आधिकारिक संसदीय दस्तावेज। विश्लेषण से पता चलता है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य की विश्वव्यापी ऊर्जा-व्यापार में प्रमुख भूमिका और 87.7 प्रतिशत कच्चा तेल आयात पर निर्भरता भारत की अर्थव्यवस्था को मूल्य और आपूर्ति झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। आयात बिल और व्यापार घाटे का विस्तार, रुपये पर दबाव, लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, चाबहार परियोजनाओं पर प्रतिबंधगत जोखिम और प्रवासी भारतीयों और प्रेषणों पर प्रभाव संभावित परिणामों में से कुछ हैं। नतीजतन, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, मूल्य-हेजिंग, रणनीतिक भंडारण और संतुलित कूटनीति भारत की आर्थिक संवेदनशीलता को कम करने के प्रमुख साधन हैं।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 16-07-2026
- **Accepted:** 29-08-2026
- **Published:** 31-08-2026
- **IJCRM:**5(4); 2026: 1010-1014
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

अहिरवार द. प्र, अहिरवार वि, नारायण प, किरार रा सिं. अमेरिका–ईरान संघर्ष और भारत पर उसके आर्थिक प्रभाव: ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, मुद्रास्फीति और भू-आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(4):1010-1014.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: अमेरिका–ईरान संघर्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, कच्चा तेल, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, भू-अर्थशास्त्र।

© 2026 दशरथ प्रसाद अहिरवार, विनीता अहिरवार, डॉ. पदम नारायण, डॉ. राजवीर सिंह किरार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

वैज्ञानिक लंबे समय से, परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन, समुद्री सुरक्षा और ईरान-समर्थित सशस्त्र बलों की भूमिका अमेरिका-ईरान के संबंधों में चर्चा का विषय रहे हैं। ईरान ने मई 2019 के बाद एक संयुक्त व्यापक कार्ययोजना के तहत अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं का क्रमिक अनुपालन कम किया और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA, 2025a) की जांच की क्षमता सीमित की। Jun. 2025 में, अमेरिका ने तीन परमाणु स्थलों (फोर्डो, नतांज और इस्फहान) पर हवाई हमले किए (IAEA, 2025b; US Department of Defense, 2025) । ऊर्जा बाजार, जहाजरानी बीमा और निवेशक जोखिम-धारणा में अनिश्चितता बढ़ी इस सैन्य विस्तार से। पश्चिम एशिया भारत के ऊर्जा आयात, समुद्री व्यापार, प्रवासी रोजगार और क्षेत्रीय संपर्क का मुख्य आधार है, इसलिए यह विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संघर्ष केवल ईरान से प्रत्यक्ष व्यापार तक नहीं जाता; डॉलर की मांग, परिवहन खर्च, राजकोषीय प्रबंधन और मौद्रिक नीति इसे पूरी अर्थव्यवस्था में फैल सकते हैं। इसलिए इसका विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र और विदेश नीति के संयोजन से किया जाना चाहिए।

2. अध्ययन का उद्देश्य

(i). अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक कीमतों और तेल एवं गैस आपूर्ति में उत्पन्न जोखिम का आकलन; (ii) भारत के आयात बिल, व्यापार घाटे, चालू खाते और रुपये पर संभावित प्रभाव का अध्ययन; **(ii)**. ईंधन मूल्य में वृद्धि से मुद्रास्फीति, उत्पादन खर्च और वित्तीय बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण; (iv) भारत-ईरान व्यापार, चाबहार बंदरगाह और मध्य एशियाई संपर्क में प्रतिबंधगत चुनौतियों का विश्लेषण; तथा (v) आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नीतिगत उपायों का प्रस्ताव करना

3. शोध-पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है और वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। 2020–2025 के बीच भारतीय सरकारी रिपोर्टों, संसदीय उत्तरों, RBI की मौद्रिक नीति रिपोर्ट, PPAC आँकड़ों, वाणिज्य विभाग, आईएएए, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन, IMF, विश्व बैंक और IOM के प्रकाशनों का इसमें उपयोग किया गया है। पद्धति में परिदृश्य-आधारित मूल्यांकन, आर्थिक संचरण-मार्गों की व्याख्या और तथ्य-आधारित तुलनात्मक विश्लेषण शामिल हैं। जब कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिलते, प्रभावों को "संभावित" या "संघर्ष के विस्तार की स्थिति में" कहा जाता है।

4. अमेरिका-ईरान संघर्ष का भू-राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ:

हॉर्मुज जलडमरूमध्य संघर्ष की आर्थिक गंभीरता से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी ईएआईए (2025a) के अनुसार, वर्ष 2024 में इस मार्ग से औसतन 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन प्रवाहित हुए, जो विश्व के पेट्रोलियम तरल उपभोग का लगभग 20 प्रतिशत था। इसी वर्ष, कतर से द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का लगभग पाँचवाँ हिस्सा वैश्विक व्यापार हुआ (US EIA, 2025b)। इसलिए जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बंद करना आवश्यक नहीं है; "भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम" सिर्फ टैंकरों पर खतरे, नौसैनिक तनाव, बंदरगाहों पर जोखिम, बीमा प्रीमियम और मार्ग परिवर्तन की आशंका से बढ़ सकता है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से भुगतान तंत्र, बैंकिंग चैनल, जहाजरानी और तेल निर्यात सब प्रभावित होते हैं। इससे बाजार को वास्तविक उपलब्धता से अधिक अनिश्चितता महसूस हो सकती है। कीमतों में अस्थायी उछाल हो सकता है अगर संघर्ष छोटा और अल्पकालिक है; किंतु बंदरगाह, पाइपलाइन या जलडमरूमध्य में लंबे समय तक व्यवधान होने पर ऊर्जा, मालभाड़ा और बीमा की कीमतें अधिक स्थायी रूप से बढ़ सकती हैं।

5. भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव:

आयात-निर्भरता भारत की ऊर्जा संरचना पर सबसे बड़ा खतरा है। संसदीय आंकड़ों के अनुसार, प्राकृतिक गैस की आयात-निर्भरता लगभग 47 प्रतिशत थी, जबकि कच्चे तेल की आयात-निर्भरता 87.7 प्रतिशत थी (Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, 2024)। Minister of Petroleum and Natural Gas, 2024) इसलिए, आयात बिल और रिफाइनरी खर्च दोनों अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्य में वृद्धि से प्रभावित होते हैं। भारतीय रिफाइनरियाँ स्रोतों को बदल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कच्चे तेल की गुणवत्ता, अनुबंध, मालभाड़ा और रिफाइनरी विन्यास अलग होने से तत्काल प्रतिस्थापन पूरी तरह से सस्ता नहीं होता।

भारत ने विशाखापत्तनम, मंगलूरु और पादुर में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल आवश्यकता) की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता विकसित की है; दूसरे चरण में 6.5 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता का अनुमान लगाया गया है (PIB, 2024a; वर्तमान समिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, 2024) लंबी लड़ाई होने पर व्यावसायिक भंडार, स्रोत-विविधीकरण और दीर्घकालीन अनुबंध भी आवश्यक होंगे, हालांकि भंडार छोटी अवधि के लिए फायदेमंद है।

6: मुद्रास्फीति और घरेलू उत्पादन खर्च

दोनों ईंधन मूल्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। डीजल, कृषि मशीनरी और माल परिवहन में; औद्योगिक ईंधन, बिजली और प्राकृतिक गैस उर्वरक में; तथा पेट्रोलियम उत्पादों को विमानन, रसायन, प्लास्टिक, पेंट और पैकेजिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मूल्यवृद्धि थोक मूल्य सूचकांक में जल्दी दिखाई दे सकती है, जो बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तक पहुंचती है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न और सब्जी, उच्च मालभाड़ा से महँगे हो सकते हैं, जिससे निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों की वास्तविक क्रय-शक्ति कम होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक का अप्रैल 2025 का परिदृश्य-अनुमान कहता है कि मुद्रास्फीति लगभग 30 आधार अंक बढ़ सकती है और वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 15 आधार अंक कम हो सकती है यदि घरेलू कीमतों में पूरी तरह से पास-थ्रू हो (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2025) सरकार उत्पाद शुल्क कम करके प्रभाव कम कर सकती है, लेकिन इससे कमाई होगी; सार्वजनिक तेल कंपनियों के लाभ और निवेश क्षमता पर दबाव पड़ सकता है अगर वे कीमतें रोकते हैं। इसलिए मुद्रास्फीति नियंत्रण, राजकोषीय संतुलन और ऊर्जा कंपनियों की वित्तीय स्थिति में नीति-विरोध पैदा होता है।

© 2026 दशरथ प्रसाद अहिरवार, विनीता अहिरवार, डॉ. पदम नारायण, डॉ. राजवीर सिंह किरार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

7. रुपये की विनिमय दर, चालू खाता और व्यापार घाटा

डॉलर में खरीदा जाता है। यदि मूल्य बढ़ता है तो समान मात्रा में आयात करने के लिए अधिक डॉलर चाहिए, जिससे चालू खाते का घाटा और व्यापार घाटा बढ़ सकता है। 2023 से 24 तक भारत का कुल वस्तु एवं सेवा आयात 856.52 अरब डॉलर था; यही कारण है कि ऊर्जा आयात में सीमित प्रतिशत की वृद्धि भी बाह्य भुगतान पर काफी दबाव डाल सकती है (व्यापार विभाग, 2025) निवेशकों की जोखिम-धारणा को कमजोर चालू खाता प्रभावित कर सकता है और रुपये पर मूल्यह्रास का दबाव बढ़ा सकता है।

"तेल–मुद्रा–मुद्रास्फीति" चक्र हो सकता है अगर रुपये का मूल्य गिरता है, तो तेल घरेलू मुद्रा में महंगा हो जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025 में एक विश्लेषण प्रकाशित किया है जो बताता है कि आधाररेखा के तुलना में रुपये में 5 प्रतिशत मूल्यह्रास मुद्रास्फीति को लगभग 35 आधार अंक बढ़ा सकता है (Reserve Bank of India, 2025) । केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में भारी अस्थिरता को नियंत्रित कर सकता है, किंतु निरंतर हस्तक्षेप से भंडार पर दबाव और ब्याज-दर नीति में जटिलता पैदा होती है।

8. भू-राजनीतिक तनाव अक्सर जोखिम-विमुखता, विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाह, बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट और इक्विटी मूल्यांकन में गिरावट का कारण बनता है, जो भारत के वित्तीय बाजार और निवेश पर प्रभाव डालता है।

तेल की बढ़ती कीमतों से विमानन, परिवहन, टायर, पेंट, रसायन, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स और तेल विपणन क्षेत्रों की लागत बढ़ सकती है। तेल विपणन कंपनियों का विपणन मार्जिन घटेगा अगर खुदरा कीमतें तुरंत न बढ़ें। घरेलू तेल और गैस उत्पादकों की आय बढ़ सकती है, लेकिन कर, उपकर और मूल्य-नियमन इसे कम कर सकते हैं।

बाजार प्रभावी होगा। सुरक्षित संपत्ति की मांग अल्पकाल में बढ़ सकती है, जबकि आयात-निर्भर कंपनियों के शेयर दबाव में आ सकते हैं। लंबी अस्थिरता उपभोक्ता विश्वास और पूँजीगत व्यय को कमजोर कर सकती है। इसलिए तेल की कीमत, संघर्ष की अवधि, डॉलर की दिशा और सरकार की कर-नीति के संयुक्त परिणामों पर वित्तीय प्रभाव निर्भर करेगा।

9. भारत-ईरान व्यापार में भुगतान, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी को कठिन बनाया गया है क्योंकि चाबहार बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

किंतु चाबहार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाकिस्तान को पार करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया से समुद्री-स्थलीय संपर्क बना सकता है। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का विकास और संचालन मई 2024 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन ने किया (PIB, 2024b)। Minister of Foreign Affairs, 2024a)

तीन प्रकार के संघर्षों से परियोजना को बचाया जाएगा: डॉलर भुगतान और वित्तपोषण में कठिनाई, अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों का पालन, और जहाजरानी और बीमा की लागत में वृद्धि फिर भी, चाबहार को छोड़ना भारत की मध्य एशियाई संपर्क रणनीति को प्रभावित करेगा। परियोजना-विशिष्ट प्रतिबंधों से छूट, पारदर्शी भुगतान प्रणाली, स्थानीय मुद्रा तंत्र और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का संस्थागत समन्वय समाधान का हिस्सा हैं।

10. खाड़ी सहयोग परिषद देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय प्रवासी, रोजगार और विदेशी प्रेषित हैं;

2024 में, संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 38.9 लाख और सऊदी अरब में लगभग 26.45 लाख भारतीय रहने का अनुमान लगाया गया था (मणिपुर विदेश मंत्रालय, 2024b) । भारत 2024 में विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता था, जो लगभग 129 अरब डॉलर था (विश्व बैंक, 2024) । संघर्ष का क्षेत्रीय विस्तार विमान सेवाओं, रोजगार, वेतन भुगतान, निकासी व्यवस्था और धन-प्रसार चैनलों को बाधित कर सकता है।

कुल प्रेषण में कमी का प्रभाव सीमित नहीं होगा। परिवारों की खपत, आवास निवेश और ऋण भुगतान केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और अन्य प्रवासी-निर्भर क्षेत्रों में प्रभावित हो सकते हैं। युद्ध के दौरान, उत्पादन और सुरक्षा के जोखिम से यह लाभ निष्प्रभावी हो सकता है, हालांकि कुछ खाड़ी देशों का सार्वजनिक व्यय तेल की कमाई से बढ़ सकता है।

11. भारत को भी संकटग्रस्त ऊर्जा नीति में सुधार का अवसर मिलता है।

भारत को रूस, अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य देशों से संतुलित आयात मिल सकता है; रणनीतिक और व्यावसायिक भंडारण को बढ़ा सकता है; और लंबी अवधि के अनुबंधों को स्पॉट बाजार खरीद के साथ जोड़ सकता है। यदि विनिमय और प्रत्यावर्तन प्रणाली विश्वसनीय हैं, तो रुपये या परस्पर स्वीकृत मुद्राओं में व्यापार करने से डॉलर-तरलता जोखिम कम हो सकता है।

मध्यम अवधि में, सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक गतिशीलता, सौर, पवन, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन की मांग कम हो सकती है। यह जोखिम-विविधीकरण है, न कि पूर्ण प्रतिस्थापन। ऊर्जा दक्षता, पेट्रोकेमिकल पुनर्चक्रण और घरेलू अन्वेषण भी आयातित हाइड्रोकार्बन पर दबाव कम कर सकते हैं।

12. पहला नीतिगत सुझाव

1. LNG और कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं, मार्गों और अनुबंध अवधियों को विविध बनाया जाए।
2. रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का दूसरा चरण तेज किया जाए और न्यूनतम परिचालन-स्टॉक मानक निर्धारित किया जाए।
3. तेल आयात पर जोखिम-सीमा, मूल्य-हेजिंग और विकल्प अनुबंधों पर स्पष्ट सार्वजनिक नीति बनाई जाए।
4. केंद्र और राज्यों द्वारा ईंधन कर समायोजन को लक्षित और अस्थायी रूप से रखा जाना चाहिए, ताकि राजस्व और मुद्रास्फीति को संतुलित रखा जा सके।
5. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच मुद्रास्फीति, तेल मूल्य और विनिमय दरों का संयुक्त परिदृश्य परीक्षण नियमित रूप से कराया जाएगा।
6. प्रतिबंध-अनुपालन, बीमा, स्थानीय मुद्रा भुगतान और परियोजना वित्त के लिए अलग-अलग प्रणाली बनाई जाएं।

© 2026 दशरथ प्रसाद अहिरवार, विनीता अहिरवार, डॉ. पदम नारायण, डॉ. राजवीर सिंह किरार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

7. भारतीयों को खाड़ी देशों में अद्यतन पंजीकरण, आपातकालीन उड़ानें, निकासी गलियारे और वेतन/प्रेषण सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाएं।
8. ऊर्जा-सुरक्षा नीति में नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन में निवेश को शामिल किया जाएगा।

13. निष्कर्ष

अमेरिका-ईरान संघर्ष भारत के लिए एक दूरस्थ सैन्य संघर्ष नहीं है; यह उसकी ऊर्जा, मूल्य-स्थिरता, बाह्य संतुलन और मानव सुरक्षा को भी जोखिम में डालता है। Jun 25, 2025 के अमेरिकी हमले ने दिखाया कि प्रतिबंध और परमाणु विवाद सैन्य टकराव में बदल सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को आपूर्ति-विघटन और जोखिम-प्रीमियम दोनों से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हॉर्मुज से विश्व तेल और LNG व्यापार का बड़ा हिस्सा होता है, और देश की 87.7 प्रतिशत कच्चे तेल आयात पर निर्भर है। आयात बिल, व्यापार घाटा और डॉलर की मांग बढ़ाते हैं जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं; रुपये की कमी आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ाती है; तथा उत्पादन और परिवहन की लागत ग्राहकों तक पहुंचती है। साथ ही खाड़ी में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और चाबहार पर प्रतिबंधगत अनिश्चितता भी नीति-चुनौतियाँ हैं।

लेकिन प्रभाव समान या अपरिहार्य नहीं है। भारत के निर्यात, प्रेषण, कूटनीतिक संबंध और विविध रिफाइनिंग क्षमता कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। तत्काल मूल्य नियंत्रण दीर्घकालिक समाधान नहीं है; यह ऊर्जा स्रोतों और मार्गों का विविधीकरण, पर्याप्त रणनीतिक भंडार, हेजिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, स्थानीय मुद्रा भुगतान और संतुलित कूटनीति में है। इस तरह, ऊर्जा संक्रमण को जलवायु नीति, समष्टि-आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के रूप में अपनाना भारत को बाह्य खतरे से स्थायी रूप से बचाने में मदद कर सकता है।

संदर्भ सूची

1. Department of Commerce. Annual report 2024–25. New Delhi: Government of India; 2025. Available from: https://www.commerce.gov.in/files/2025-08/Commerce_AR-2024-25-English-1.pdf
2. International Atomic Energy Agency. Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security Council resolution 2231 (2015) (GOV/2025/24). Vienna: International Atomic Energy Agency; 2025. Available from: https://www.iaea.org/sites/default/files/25/06/gov2025-24.pdf
3. International Atomic Energy Agency. Update on developments in Iran (5). Vienna: International Atomic Energy Agency; 2025 Jun 22. Available from: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-on-developments-in-iran-5
4. International Atomic Energy Agency. Director General Grossi's statement to the UN Security Council on the situation in Iran. Vienna: International Atomic Energy Agency; 2025 Jun 22. Available from: https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-general-grossis-statement-to-unsc-on-situation-in-iran-22-june-2025
5. International Monetary Fund. External sector report 2024: imbalances receding amid elevated uncertainty. Washington, DC: International Monetary Fund; 2024. Available from: https://www.imf.org/en/Publications/ESR/Issues/2024/07/12/external-sector-report-2024
6. International Monetary Fund. India: 2024 Article IV consultation—press release; staff report; and statement by the executive director for India. Country Report No. 25/54. Washington, DC: International Monetary Fund; 2025. Available from: https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/002/2025/054/002.2025.issue-054-en.pdf
7. International Organization for Migration. World migration report 2024. Geneva: International Organization for Migration; 2024. Available from: https://worldmigrationreport.iom.int/msite/wmr-2024-interactive/
8. Ministry of External Affairs. Question No. 44: Chabahar Port Project. New Delhi: Government of India; 2024. Available from: https://www.mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/38631/QUESTION+NO+44+CHABAHAR+PORT+PROJECT
9. Ministry of External Affairs. Question No. 1996: Expatriates in GCC countries. New Delhi: Government of India; 2024. Available from: https://www.mea.gov.in/rajya-sabha?dtl/38746/QUESTION_NO_1996_EXPATRIATES_IN_GCC_COUNTRIES
10. Ministry of Petroleum and Natural Gas. Rajya Sabha Unstarred Question No. 130: Energy demand. New Delhi: Government of India; 2024 Nov 25. Available from: https://sansad.in/getFile/annex/266/AU130_uS1Dpk.pdf?source=pqars
11. Petroleum Planning & Analysis Cell. Snapshot of India's oil and gas data: December 2024. New Delhi: Ministry of Petroleum and Natural Gas; 2024. Available from: https://ppac.gov.in/download.php?file=rep_studies%2F1737011904_Snapshot-of-Indias-Oil-and-Gas-Data_WebUpload_December-2024_compressed.pdf
12. Press Information Bureau. Yearend review 2024—Ministry of Petroleum and Natural Gas. New Delhi: Government of India; 2024 Dec 31. Available from: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2090844
13. Press Information Bureau. Long-term main contract for development of Shahid Beheshti Port Terminal, Chabahar signed between IPGL and PMO of Iran. New Delhi: Government of India; 2024 May 13. Available from: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2020454
14. Press Information Bureau. India's petroleum industry. New Delhi: Government of India; 2025 Jan 27. Available from:

© 2026 दशरथ प्रसाद अहिरवार, विनीता अहिरवार, डॉ. पदम नारायण, डॉ. राजवीर सिंह किरार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2096817
15. Reserve Bank of India. Monetary policy report—April 2025. Mumbai: Reserve Bank of India; 2025. Available from: https://www.rbi.org.in/hindi1/Upload/Publications/PDFs/MPRApril2025_09042025.pdf
16. Standing Committee on Petroleum and Natural Gas. Demands for grants (2024–25): Ministry of Petroleum and Natural Gas. First Report, 18th Lok Sabha. New Delhi: Parliament of India; 2024. Available from: https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Petroleum%20%26%20Natural%20Gas/18_Petroleum_And_Natural_Gas_1.pdf?source=loksabhadocs
17. U.S. Department of Defense. Hegseth, Caine laud success of U.S. strike on Iran nuclear sites. Arlington, VA: U.S. Department of Defense; 2025 Jun 22. Available from: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/4222533/hegseth-caine-laud-success-of-us-strike-on-iran-nuke-sites/
18. U.S. Energy Information Administration. Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint. Washington, DC: U.S. Energy Information Administration; 2025 Jun 16. Available from: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65504
19. U.S. Energy Information Administration. About one-fifth of global liquefied natural gas trade flows through the Strait of Hormuz. Washington, DC: U.S. Energy Information Administration; 2025 Jun 24. Available from: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65584
20. World Bank. In 2024, remittance flows to low- and middle-income countries are expected to reach $685 billion. Washington, DC: World Bank; 2024 Dec 18. Available from: https://blogs.worldbank.org/en/peoplemove/in-2024--remittance-flows-to-low--and-middle-income-countries-ar

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

दशरथ प्रसाद अहिरवार अर्थशास्त्र विषय में शोधार्थी हैं और महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश, भारत से संबद्ध हैं। उनकी अकादमिक रुचि अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों तथा समकालीन आर्थिक नीतियों के अध्ययन में है। वे शोध एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से आर्थिक विषयों की समझ को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

© 2026 दशरथ प्रसाद अहिरवार, विनीता अहिरवार, डॉ. पदम नारायण, डॉ. राजवीर सिंह किरार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/